मणिपुर सरकार

बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ

अगस्त, 2025

बजट का केंद्र बिंदु

सामाजिक क्षेत्र पर जोर
कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार
प्रमुख क्षेत्र
सुरक्षा, कानून और व्यवस्था
बुनियादी ढांचे पर केंद्र बिंदु
आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की राहत और पुनर्वास

बुनियादी ढांचे पर केंद्र बिंदु

पूंजीगत परिव्यय

- पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि.
- 2025-26 (बजट अनुमान) के दौरान, पूंजीगत परिव्यय 2024-25 के पूर्व-वास्तविक अनुमानों की तुलना में 49% तक बढ़ने का अनुमान है

एसएएससीआई

- एसएएससीआई के तहत राज्य को लगभग 3000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं
- एसएएससीआई की निरंतरता से पूंजीगत व्यय वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा

परिसंपत्ति निर्माण हेतु निधि

- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत 9647 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं
- नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) - 124 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाएं पूरी हुईं
- पीएम डिवाइन के तहत 450 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं को मंजूरी

सामाजिक क्षेत्र पर जोर

2025-26 के लिए सामाजिक क्षेत्र परिव्यय: 5348 करोड़ रुपये

- सामाजिक कल्याण आवंटन = 864 करोड़ रुपये
- एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक आवंटन = 175 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य आवंटन = 1358 करोड़ रुपये
- शिक्षा आवंटन = 2951 करोड़ रुपये

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास

राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास - **सरकार की प्राथमिकता**

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 628 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया

सुरक्षा, कानून और व्यवस्था

सुरक्षा, कानून और व्यवस्था - प्रगति	
संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए प्रोत्साहन	2025-26 के लिए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन **3654 करोड़** रुपये है

कनेक्टिविटी का निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार

कनेक्टिविटी का निर्माण

- दो ईएपी परियोजनाएं - इम्फाल रिंग रोड और इम्फाल शहर में कंक्रीट फुटपाथ
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण आरआईडीएफ निधि के अंतर्गत किया गया
- भारत सरकार द्वारा 92 सड़कों के लिए 314 करोड़ रुपये के सीआरआईएफ वित्तपोषण को मंजूरी दी गई
- एसएएससीआई के तहत सड़क निवेश को छोड़कर, 2025-26 के लिए सड़कों, पुलों और भवन के लिए बजटीय आवंटन 605 करोड़ रुपये है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

- प्रमुख परियोजना: न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित लमफेलपात जलाशय - बाढ़ नियंत्रण और अतिरिक्त पेयजल का दोहरा उद्देश्य
- परियोजना लागत: 650 करोड़ रुपये
- 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन: 405 करोड़ रुपये

- 2025-26 के लिए पेयजल और स्वच्छता के लिए **630 करोड़ रुपये** का आवंटन किया गया है।
- दो ईएपी परियोजनाओं - एकीकृत सीवरेज परियोजना इम्फाल शहर चरण II और मणिपुर जलापूर्ति योजना - के लिए 450 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियां

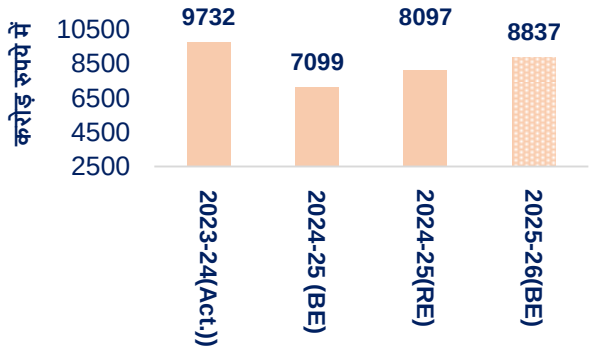

राजस्व प्राप्तियां

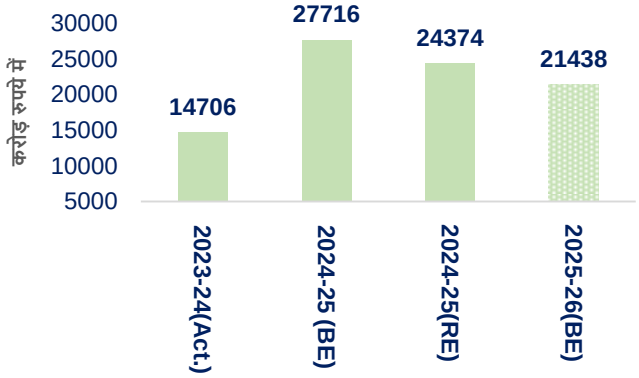

व्यय

राजस्व व्यय

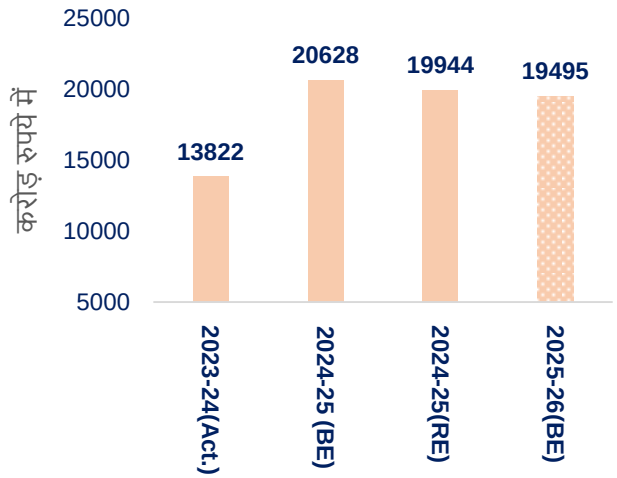

पूंजीगत व्यय

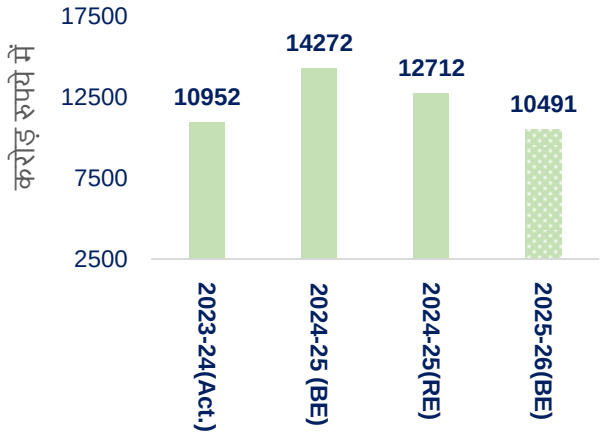

रुपया कहाँ से आता है

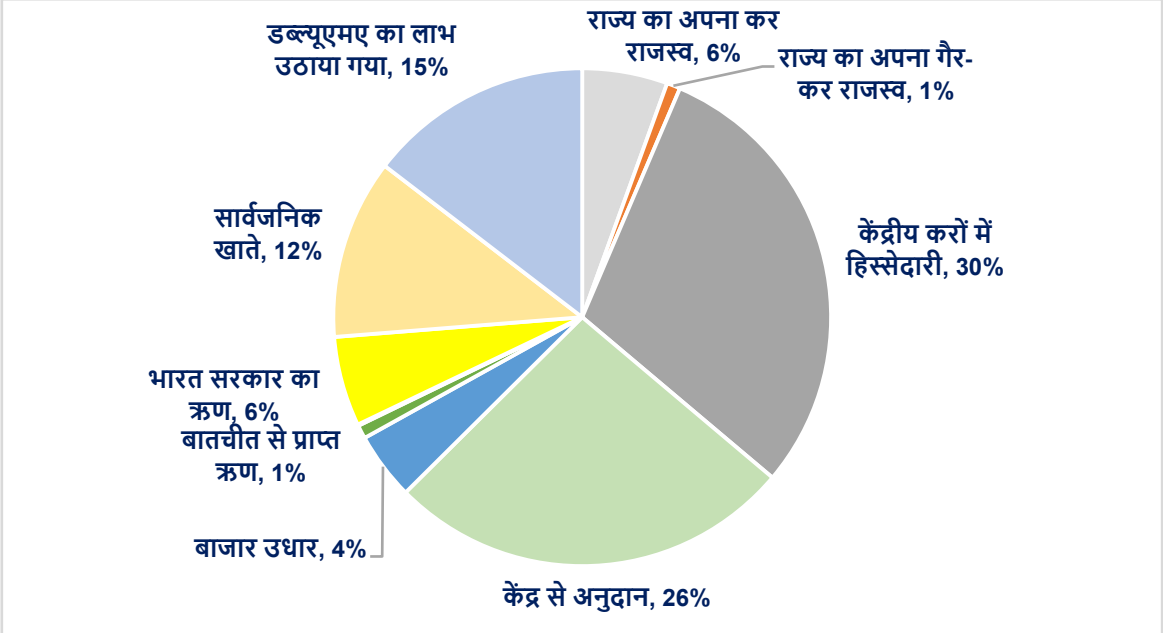

(नोट: आंकड़े % में हैं तथा कुल प्राप्तियों में इसका हिस्सा दर्शाते हैं)

रुपया कहाँ जाता है

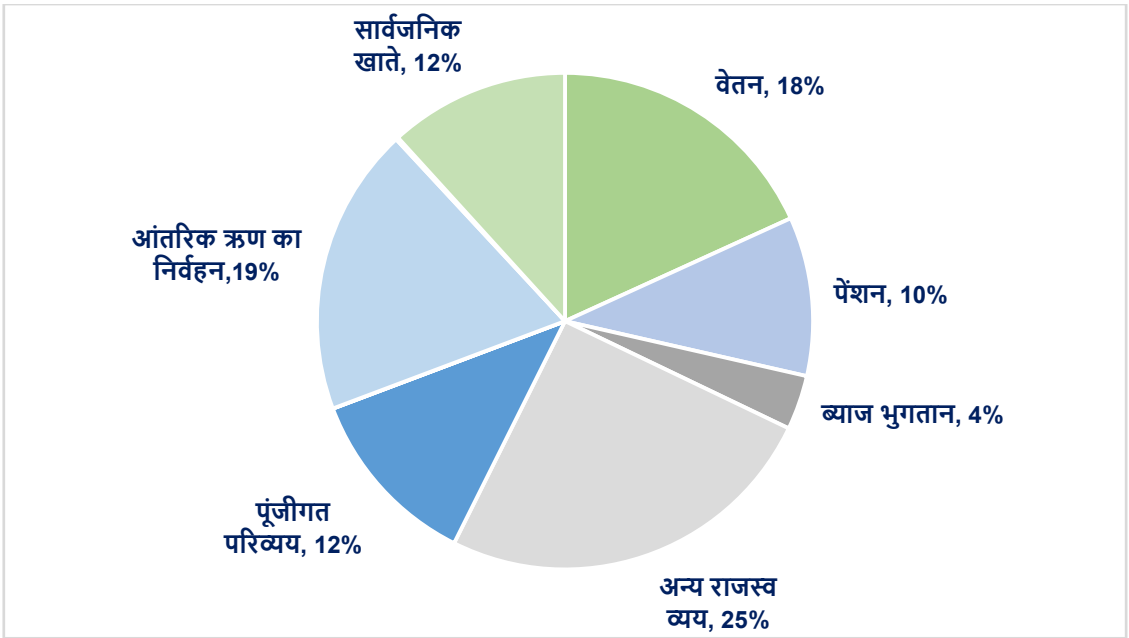

(नोट: आंकड़े % में हैं तथा कुल व्यय में इसका हिस्सा दर्शाते हैं)

राजकोषीय घाटे के रुझान (जीएसडीपी के % के रूप में)

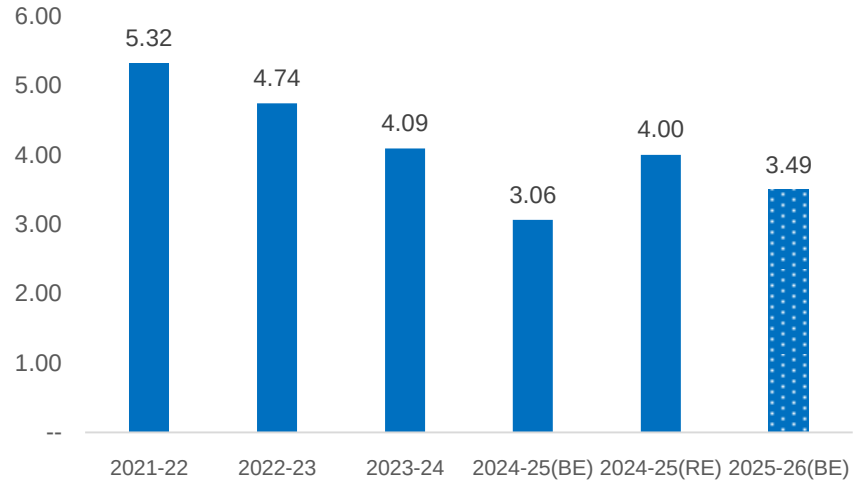

बकाया ऋण प्रवृत्तियाँ (जीएसडीपी के % के रूप में)

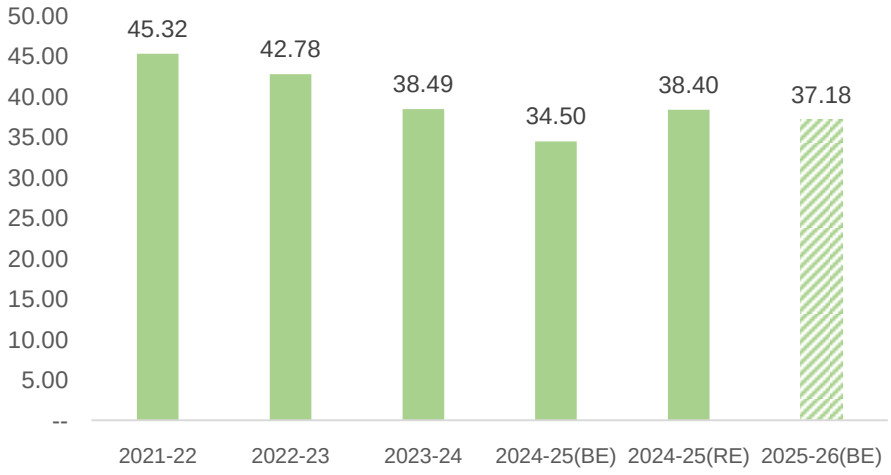

राजस्व अधिशेष रुझान (जीएसडीपी के % के रूप में)

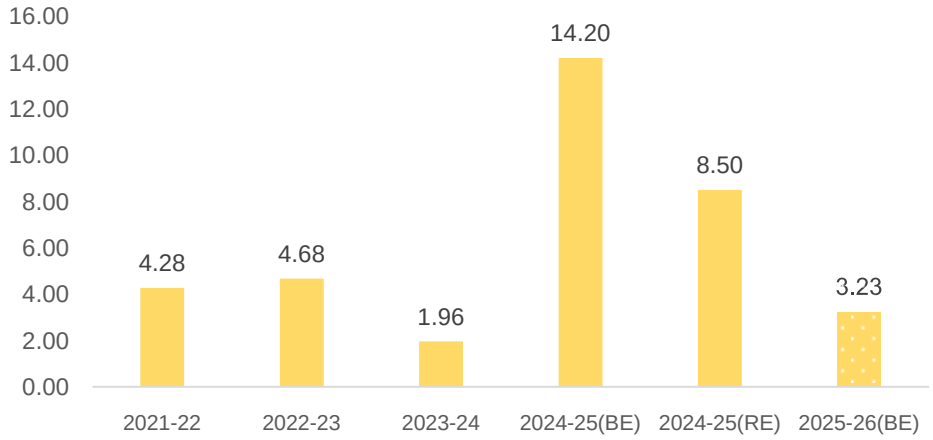

विशेष अनुदान

इस बजट में भारत सरकार मणिपुर को आर्थिक सुधार में सहायता के लिए 2198 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज प्रदान कर रही है। इसमें आंतरिक रूप से विस्थापित उन लोगों के लिए सहायता, पुनर्वास प्रयासों के लिए परिसंपत्ति निर्माण, सुरक्षा व्यय और उच्च ब्याज वाले ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल है। इसके अलावा, राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने हेतु (एसएएससीआई) के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया गया है। 2898 करोड़ रुपये का कुल विशेष अनुदान मणिपुर को आर्थिक सुधार की दिशा में काम करने में बड़ी सहायता प्रदान करेगा।

बुनियादी ढांचे पर केंद्र बिंदु

व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हाल के वर्षों में, पूंजीगत परिव्यय पर व्यय 2017-18 में जीएसडीपी के 6% से बढ़कर 2022-23 में जीएसडीपी के 9% हो गया है। 2016-17 से 2022-23 के बीच पूंजीगत परिव्यय पर व्यय 1428 करोड़ रुपये से बढ़कर 3484 करोड़ रुपये हो गया। 2025-26 के दौरान, हमारा लक्ष्य इस मद पर व्यय को बढ़ाकर 4040 करोड़ रुपये करना है, जो 2024-25 के पूर्व-वास्तविकों की तुलना में 49% अधिक है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई), 50-वर्षीय अवधि का ब्याज मुक्त ऋण, जिसे भारत सरकार ने 2020-21 में शुरू किया था, पूंजीगत परिव्यय पर व्यय बढ़ाने में एक सक्षम कारक है। अब तक राज्य को इस योजना के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। एसएएससीआई के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए किया गया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सिंचाई, संपर्क और सुरक्षा आदि शामिल हैं। कुछ परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं। भारत सरकार द्वारा 2025-26 के दौरान इस योजना को जारी रखने से बुनियादी ढाँचे पर व्यय को और बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। 2025-26 के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर कुल व्यय 5348 करोड़ रुपये है। इसमें से सबसे अधिक आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है, उसके बाद स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किया गया है।

प्राथमिकता वाले सामाजिक क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन
(करोड़ रुपये में)

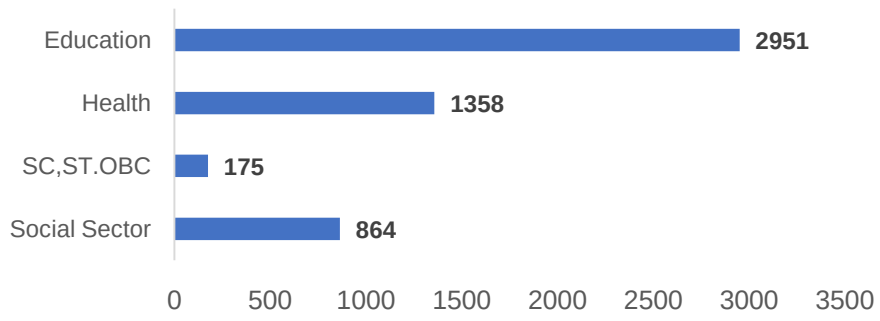

वर्तमान बजट में राहत कार्यों, अस्थायी रूप से विस्थापितों के लिए अस्थायी आश्रयों के निर्माण, मुआवजा, पुनर्वास आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु **628 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है।

सुरक्षा, कानून और व्यवस्था

सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन **3654 करोड़ रुपये** है।

कनेक्टिविटी का निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार।

मणिपुर के संदर्भ में, कनेक्टिविटी का निर्माण और सड़क अवसंरचना में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अंतर्गत, दो परियोजनाएँ कार्यान्वित की जानी हैं - इम्फाल रिंग रोड और इम्फाल शहर में फुटपाथ सहित कंक्रीट सड़क। इसके अलावा, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत नाबार्ड वित्तपोषण के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तपोषण के तहत भी अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एसएएससीआई के तहत सड़क निवेश को छोड़कर, 2025-26 के लिए कनेक्टिविटी निर्माण के लिए कुल बजटीय आवंटन 605 करोड़ रुपये है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 2025-26 के लिए 405 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।. ईएपी के तहत, न्यू डेवलपमेंट बैंक लमफेलपात जलाशय पुनरुद्धार परियोजना को वित्तपोषित कर रहा है। इस परियोजना से इम्फाल शहर में बार-बार आने वाली बाढ़ कम होगी और उपभोग के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।

पेयजल लोगों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत 630 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। दो चालू परियोजनाओं - एकीकृत सीवरेज परियोजना इम्फाल शहर चरण II और मणिपुर जलापूर्ति योजना - के लिए ईएपी निधि के रूप में 450 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय है।